

भारत का पहला साँवरेन ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क

प्रलिस के लयि:

साँवरेन ग्रीन बॉण्ड की वशिषताएँ, साँवरेन ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क

मेन्स के लयि:

साँवरेन ग्रीन बॉण्ड, बजट के तहत घोषणा, ग्रीन बॉण्ड की स्थति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वतित और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने भारत के पहले [साँवरेन ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क](#) को मंजूरी दी है।

- हरति परयोजनाओं के लयि संसाधन जुटाने हेतु साँवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी कयि जाएंगे।

साँवरेन ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क:

- यह फ्रेमवर्क 'पंचामृत' के तहत भारत की परतबिद्धताओं के नकशेकदम पर मंजूरी दी गई है, जैसा कनिंबर, 2021 में ग्लासगो में 'COP26' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पष्ट कयि गया था।
- इस मंजूरी से [पेरिस समझौते](#) के तहत अपनाए गए अपने [राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(NDC\)](#) लक्ष्यों के परतभारत की परतबिद्धता और भी अधिक मज़बूत होगी।
- साँवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करने हेतु लयि गए महत्त्वपूर्ण नरिण्यों का अनुमोदन करने के लयि [हरति वतित कार्यकारी समति \(GFWC\)](#) का गठन कयि गया है।
- व्यापक वचिर-वमिरश करने और गंभीरतापूर्वक गौर करने के बाद [CICERO](#) ने भारत के ग्रीन बॉण्ड की रूपरेखा को 'गुड' गवर्नेंस स्कोर के साथ 'मीडियम ग्रीन' की रेटगि दी है।
 - 'मीडियम ग्रीन' रेटगि उन परयोजनाओं और समाधानों को दी जाती है जो दीर्घकालिक दृष्टि की दशा में महत्त्वपूर्ण कदमों का परतनिधित्व करते हैं।
- सभी जीवाशम ईधन से संबंधति परयोजनाओं को बायोमास आधारति नवीकरणीय ऊर्जा परयोजनाओं के साथ ढाँचे से बाहर रखा गया है जो 'संरक्षति क्षेत्रों' से फीडस्टॉक पर नरिभर हैं।

साँवरेन ग्रीन बॉण्ड:

- परचिय:
 - ग्रीन बॉण्ड वभिनिन कंपनयिों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा वशिष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परयोजनाओं को वतितपोषति करने हेतु जारी कयि जाते हैं और नविशकों को नशिचति आय भुगतान परदान करते हैं।
 - इन परयोजनाओं में [नवीकरणीय ऊर्जा](#), स्वच्छ परविहन एवं हरति भवन आदि शामिल हो सकते हैं।
 - ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त आय को [हरति परयोजनाओं के लयि परयोग कयि जाता है](#)। यह अनय मानक बॉण्डों के वपिरित है, जसिको आय जारीकर्त्ता के वविक पर वभिनिन उद्देश्यों हेतु उपयोग कयि जा सकता है।
 - लंदन स्थति 'क्लाइमेट बॉण्ड्स इनशिपिटिवि' के अनुसार, वर्ष 2020 केअंत तक [24 राष्ट्रीय सरकारों ने कुल मलिकर 111 बलियिन डॉलर के संप्रभु ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबलिटि बॉण्ड जारी कयि थे](#)।
- साँवरेन ग्रीन बॉण्ड के लाभ:
 - साँवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करना सरकारों और नयामकों को जलवायु कार्रवाई और सतत् वकिस संबंधी मंशा का एक परबल संकेत भेजता है।
 - अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ([International Energy Agency-IEA](#)) ने वरल्ड एनर्जी आउटलुक (WEO) रपिर्ट, 2021 में अनुमान लगाया है कशिुद्ध-शूनय की प्राप्ति के लयि अतरिकित 4 ट्रिलियन डॉलर के व्यय में से 70% वकिसशील अर्थव्यवस्थाओं के

लिये आवश्यक होगा। इस दृष्टिकोण से साँवरेन बॉण्ड जारी किया जाना पूंजी के इन बड़े प्रवाहों को गति देने में सहायता कर सकता है।

- एक साँवरेन ग्रीन बेंचमार्क के विकास से अंततः अंतरराष्ट्रीय नविशकों से हरति बॉण्ड जुटाने के एक जीवंत पारितंत्र का निर्माण हो सकता है।

■ स्थिति:

◦ वैश्विक स्थिति:

- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (Environmental, Social and Governance- ESG) फंड या ईएसजी फंड लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसमें यूरोप लगभग आधी हिससेदारी रखता है।
- अनुमान है कि वर्ष 2025 तक परबंधन के तहत कुल वैश्विक परसिंपत्तिका लगभग एक-तहिई भाग ESG परसिंपत्तिका होगा।
- ईएसजी डेट फंड (ESG debt funds) की हिससेदारी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें से 80% से अधिक 'पर्यावरणीय' या ग्रीन बॉण्ड हैं और शेष सामाजिक एवं संवहनीयता बॉण्ड (Social and Sustainability Bonds) हैं।

◦ राष्ट्रीय स्थिति:

- जलवायु कार्रवाई के लिये वैश्विक पूंजी जुटाने के क्षेत्र में कार्र्यरत एक अंतरराष्ट्रीय संगठन 'क्लाइमेट बॉण्ड्स इनशिएटिवि' के अनुसार, भारतीय संस्थानों ने 18 बिलियन डॉलर से अधिक के ग्रीन बॉण्ड जारी किये हैं।

बजट में घोषित जलवायु कार्रवाई पर अन्य उपाय क्या हैं?

- बजट में जलवायु कार्रवाई पर कई उपाय शामिल थे, जैसे:

◦ बैटरी सवैपगि नीति

- उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिये पीएलआई योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन।
- सरकार एक नया वधियक पेश कर रही है जिसका उद्देश्य भारत में कार्बन बाजार के लिये एक नयामक ढाँचा प्रदान करना है ताकि ऊर्जा मशिरण में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (पीवाईक्यू)

प्रश्न. भारत सरकार की बॉण्ड यीलड नमिनलखिति में से कसिसे प्रभावति होती है? (2021)

1. युनाइटेड स्टेट्स फेडरल रज़िर्व की कार्रवाईयों से।
2. भारतीय रज़िर्व बैंक के कार्र्य से।
3. मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज़ दरों के कारण।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- बॉण्ड पैसा उधार लेने का साधन है। कसिी देश की सरकार या कसिी कंपनी द्वारा धन जुटाने के लिये बॉण्ड जारी किया जा सकता है।
- बॉण्ड यीलड वह रटिरन है जो एक नविशक को बॉण्ड पर मलिता है। प्रतफिल की गणना के लिये गणतीय सूत्र बॉण्ड के मौजूदा बाज़ार मूल्य से वभिाजति वार्षिक कूपन दर है।
- प्रतफिल में उतार-चढ़ाव ब्याज़ दरों के रुझान पर नरिभर करता है, इसके परणामस्वरूप नविशकों को पूंजीगत लाभ या हानि हो सकती है।
- बाज़ार में बॉण्ड यीलड बढ़ने से बॉण्ड की कीमत नीचे आ जाएगी।
- बॉण्ड यीलड में गरिावट से नविशक को फायदा होगा क्योंकि बॉण्ड की कीमत बढ़ेगी, जसिसे पूंजीगत लाभ होगा।
- फेड टेपरगि अमेरिकी फेडरल रज़िर्व के बॉण्ड खरीद कार्र्यक्रम में क्रमिकि कमी हुई है। इसलिये युनाइटेड स्टेट्स फेडरल रज़िर्व की कोई भी कार्रवाई भारत में बॉण्ड यीलड को प्रभावति करती है। अतः कथन 1 सही है।
- सरकारी बॉण्ड का प्रतफिल नरिधारति करने में RBI की कार्रवाईयों महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिती हैं। अरथव्यवस्था में ब्याज़ दरों की एक वसितृत शृंखला को प्रभावति करने में मौद्रिकि नीति के लिये संप्रभु यीलड वक्कर का वशिष महत्त्व है। अतः कथन 2 सही है।
- मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज़ दरें भी सरकारी बॉण्ड यीलड को प्रभावति करती हैं। अतः कथन 3 सही है।

अतः वकिल्प (d) सही है।

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में दखिने वाले 'आइएफसी मसाला बॉण्ड (IFC Masals Bonds)' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. अंतर्राष्ट्रीय वित्त नगिम (इंरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन), जो इन बॉण्डों को प्रस्तावति करता है, वशिव बैंक की एक शाखा है ।
2. ये रुपया अंकति मूल्य वाले बॉण्ड (Rupee-denominated Bonds) हैं और सार्वजनकि एवं नजिी क्षेत्र के ःण वतितियन के स्रोत हैं ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- वशिव बैंक समूह, जो क विकासशील देशों को वतितिय और तकनीकी सहायता का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, में पाँच वशिषिट लेकनि पूरक संगठन शामिल हैं
- पुनर्रमाण और विकास के लयि अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) ।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) ।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त नगिम (IFC) । **अतः कथन 1 सही है ।**
- बहुपक्षीय नविश गारंटी एजेंसी (MIGA) ।
- नविश वविादों के नपिटान के लयि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) ।
- IFC में सदस्यता केवल वशिव बैंक के सदस्य देशों के लयि खुली है । इसका बोरड वर्ष 1956 में स्थापति कयि गया था । IFC का स्वामतिव 184 सदस्य देशों के पास है, जो सामूहकि रूप से नीतयिों को नरिधारति करते हैं । बोरड ऑफ गवरनर्स और नदिशक मंडल के माध्यम से सदस्य देश IFC के कार्यक्रमों एवं गतविधियिों का मार्गदर्शन करते हैं ।
- मसाला बॉण्ड भारत के बाहर जारी कयि गए बॉण्ड होते हैं, लेकनि स्थानीय मुद्रा की बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा में नरिदषिट कयि जाता है । मसाला का अर्थ है 'मसाले' और इस शब्द का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय वित्त नगिम (IFC) द्वारा वदिशी प्लेटफॉर्मों पर भारत की संस्कृतिव व्यंजनों को लोकप्रयि बनाने के लयि कयि गया था । मसाला बॉण्ड का उद्देश्य भारत में बुनयिादी ढाँचा परयिोजनाओं को वतितपोषति करना, उधार के माध्यम से आंतरकि विकास को बढ़ावा देना तथा भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है । **अतः कथन 2 सही है ।**

अतः वकिलप (C) सही उत्तर है ।

[स्रोत: पी. आई. बी](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-first-sovereign-green-bonds-framework>